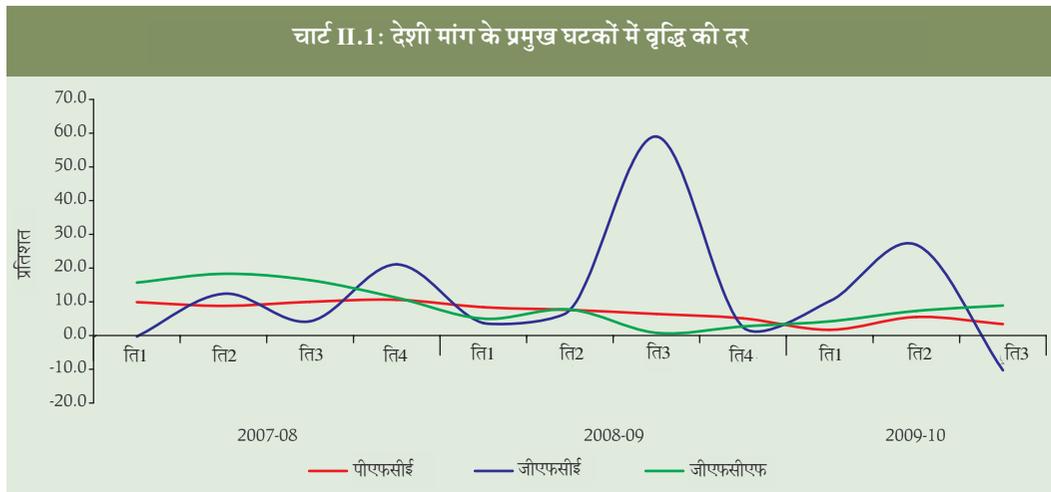


## II. समग्र मांग

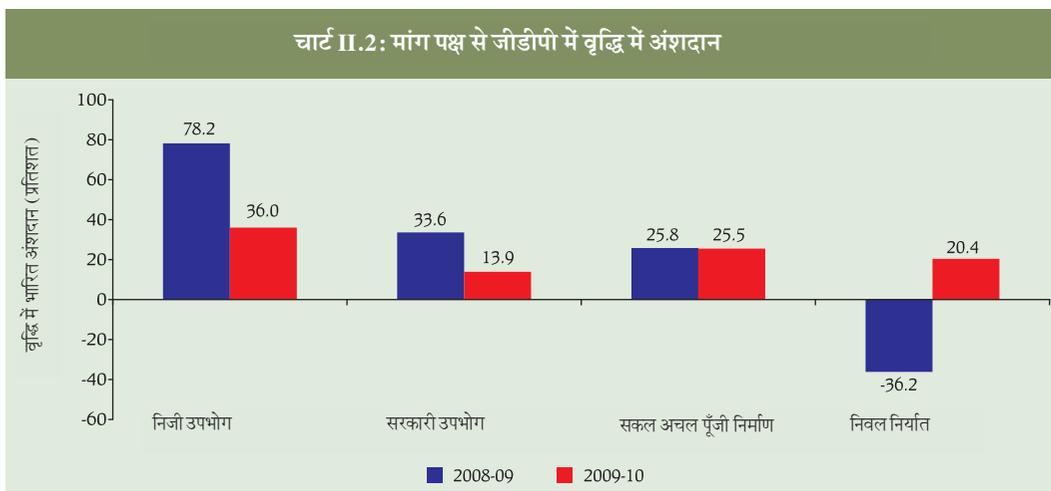
वर्ष 2009-10 में निजी उपभोग मांग में कमी आयी, जबकि सरकारी उपभोग व्यय की वृद्धि में गिरावट देखी गयी। इसके परिणामस्वरूप, उपभोग मांग, जो समग्र मांग के लगभग 70 प्रतिशत के लिए जिम्मेवार होती है, के बारे में यह अनुमान है कि इसमें वर्ष 2009-10 में 4.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सकल अचल पूँजी निर्माण में वृद्धि के रूप में निवेश मांग में वह सुधार बना रहा, जो पिछली कुछ तिमाहियों में देखा गया था, हालाँकि इसकी वृद्धि-दर वैश्विक संकट के पूर्व की अवधि के दौरान देखी गयी वृद्धि-दर के नीचे बनी रही। कारपोरेट विक्रय के क्षेत्र में वृद्धि में वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही में बड़ा उछाल देखा गया। राजकोषीय विकास, जैसाकि केंद्र के वर्ष 2010-11 के बजट में आयोजना की गयी है, समग्र मध्यावधि वृद्धि संबंधी दृष्टिकोण में सुधार में योगदान करेगा, भले ही राजकोषीय समायोजन की गुणवत्ता पर बड़ा जोर दिया जाना आवश्यक हो। निजी उपभोग और निवेश मांग में सुदृढ़तर तेजी से यह उम्मीद है कि वह वृद्धि में सुधार को प्रेरित करती रहेगी और उसे बनाये रखेगी।

II.1 सुधार के चरण के दौरान निजी उपभोग एवं निवेश मांग में रुझान महत्वपूर्ण हो जाते हैं, न केवल सुधार की ताकत के संबंध में जानकारी देने के लिए, वरन् नीतिगत विकास के समय-निर्धारण एवं गति को अनुकूलित करने के लिए। निजी उपभोग मांग में वृद्धि में वर्ष 2009-10 में नरमी आयी, जबकि सरकार के उपभोग व्यय में वृद्धि में महत्वपूर्ण रूप से गिरावट देखी गयी (चार्ट II.1)। सकल अचल पूँजी निर्माण में वृद्धि के रूप में निवेश मांग में पूर्ववर्ती चार तिमाहियों में देखा गया क्रमिक सुधार बना रहा। तथापि, वर्ष 2003-08 के दौरान पूँजी निर्माण में देखी गयी महत्वपूर्ण तेजी की तुलना में यह सुधार अब भी कम दिखाई पड़ता है। वर्ष 2009-10 के दौरान निवल निर्यात ने पूर्ववर्ती वर्ष के विपरीत जीडीपी के मांग पक्ष में धनात्मक योगदान किया (चार्ट II.2)।



II.2 कारपोरेट कार्यसंपादन के संबंध में आँकड़े विक्रय की तुलना में इन्वेंटरी स्टॉक के अनुपात में नरमी की ओर इंगित करते हैं, भले ही उसका कारण विक्रय-वृद्धि में पिछली चार तिमाहियों में महत्वपूर्ण गिरावट के बाद वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही में आया मजबूत उछाल रहा हो। हाल के महीनों में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आइआइपी) के अनुसार उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में तगड़ा सुधार कारपोरेट विक्रय में तेजी के साथ-साथ मांग पक्ष जीडीपी के आँकड़ों में नरम वृद्धि की तुलना में उपभोग मांग में

तगड़े पुनरुत्थान की ओर संकेत करता है। इस संदर्भ में, समग्र मांग पक्ष जीडीपी आँकड़ों में कृषि की वृद्धि के फलस्वरूप उद्भूत मांग की अत्यधिक भारिता को और उपभोग मांग के अन्य प्रासंगिक संकेतकों की ओर निर्दिष्ट करने की सहबद्ध आवश्यकता को पहचानना होगा, ताकि नीति संबंधी अनुमान निकाले जा सकें। वर्ष 2010-11 के लिए केंद्रीय बजट में आयोजित सरकारी व्यय में महत्वपूर्ण गिरावट के मद्देनजर निजी मांग में और भी तेजी अब तक देखे गये सुधार को बनाये रखने के लिए महत्वपूर्ण होगी।



## देशी मांग

II.3 नयी राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी शृंखला (आधार : 2004-05) के अनुसार, वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए उपादान लागत पर जीडीपी की वृद्धि-दर बाजार-कीमत पर जीडीपी की वृद्धि दर की तुलना में ऊँची रही है, जो निवल अप्रत्यक्ष करों (अर्थात्, अप्रत्यक्ष कर राजस्व घटाव आर्थिक सहायता) में कमी पर राजकोषीय उद्दीपक उपायों के प्रभाव को प्रतिबिंबित करता है। निजी और सरकारी उपभोग व्यय में पिछले वर्ष की तुलना में न्यूनतर दर से वृद्धि होने का अनुमान है (सारणी II.1)। कृषि उत्पादन में कमी ने वर्ष 2009-10 में निजी उपभोग मांग को प्रभावित किया, जो हाल की अवधि में उपभोक्ता गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में दुर्बलता में भी प्रतिबिंबित होता है। बाजार कीमतों (वर्ष 2004-05

की कीमतें) पर जीडीपी में उपभोग व्यय का समग्र हिस्सा, जो वर्ष 2008-09 में 70.9 प्रतिशत था, वह वर्ष 2009-10 में गिर कर 69.6 प्रतिशत रह गया। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि समग्र जीडीपी वृद्धि में उपभोग व्यय (निजी और सरकारी, दोनों) का योगदान, जो वर्ष 2008-09 में 111.8 प्रतिशत था, के वर्ष 2009-10 में कम हो कर लगभग 50 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है, जिसमें निजी और सरकारी उपभोग मांग, दोनों के कम होने का अनुमान लगाया गया है (चार्ट II.2)। सकल अचल पूँजी निर्माण का योगदान लगभग अपरिवर्तित है। समग्र वृद्धि में योगदान का शेष भाग निवल निर्यात (वस्तु और सेवाओं का) के पैटर्न में तीव्र पुनरुत्थान के परिणामस्वरूप अनुमानित है। समग्र दृष्टि से, जबकि आयात के निर्यात से बढ़ने की उम्मीद है, वर्ष 2009-10 में आयात-वृद्धि

सारणी II.1: जीडीपी का मांग पक्ष (2004-05 के मूल्यों पर)

मद	2008-09*	2009-10#	(प्रतिशत)									
			2008-09				2009-10			अप्रैल-दिसंबर		
			ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	2008-09	2009-10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
<b>वृद्धि दर</b>												
बाजार मूल्यों पर वास्तविक जीडीपी	5.1	6.8	7.0	6.9	3.1	4.0	6.1	6.8	5.9	5.5	6.3	
कुल अंतिम खपत व्यय	8.3	4.8	7.7	7.6	13.2	4.6	2.9	8.4	0.9	9.7	3.9	
(i) निजी अंतिम खपत व्यय	6.8	4.1	8.4	7.6	6.4	5.1	1.7	5.5	3.4	7.4	3.5	
(ii) सरकारी अंतिम खपत व्यय	16.7	8.2	3.7	7.5	59.0	2.5	10.2	26.9	-10.3	23.5	5.8	
सकल अचल पूँजी निर्माण	4.0	5.2	5.0	7.7	0.8	2.7	4.2	7.3	8.9	4.4	6.9	
स्टॉक में परिवर्तन	-61.2	4.7	-60.2	-60.3	-61.9	-62.2	3.2	-45.4	-41.4	-60.8	-28.0	
निवल निर्यात	40.2	-22.4	31.2	101.0	77.7	-29.4	26.7	10.0	-25.1	71.3	1.2	
<b>सापेक्षिक हिस्सा</b>												
कुल अंतिम खपत व्यय	70.9	69.6	71.9	69.4	75.1	67.4	69.8	70.4	71.6	72.2	70.6	
(i) निजी	59.5	58.0	61.4	60.1	61.5	55.3	58.9	59.4	60.0	61.0	59.5	
(ii) सरकारी	11.5	11.6	10.5	9.2	13.7	12.1	10.9	11.0	11.6	11.2	11.2	
सकल अचल पूँजी निर्माण	32.9	32.5	32.7	34.9	31.7	32.6	32.1	35.1	32.6	33.1	33.2	
स्टॉक में परिवर्तन	1.3	1.3	1.4	1.4	1.3	1.3	1.4	0.7	0.7	1.4	0.9	
निवल निर्यात	-6.1	-4.5	-5.2	-8.8	-7.3	-3.5	-6.3	-9.0	-5.1	-7.1	-6.8	
<b>ज्ञापन :</b>												
बाजार मूल्य पर वास्तविक सकल देशी उत्पाद (करोड़ रुपये)	4465360	4767142	1042528	1057115	1159298	1206421	1105641	1129182	1228201	3258941	3463024	
*: त्वरित अनुमान #: संशोधित अनुमान।												
<b>नोट:</b> चूंकि प्रमुख मर्दें ही सारणी में शामिल की गई हैं, इसलिए आंकड़ों का जोड़ 100 नहीं होगा।												
<b>स्रोत:</b> केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन।												

में गिरावट निर्यात-वृद्धि की तुलना में अधिक रही है। इसके परिणामस्वरूप, निवल निर्यात का हिस्सा, जो वर्ष 2008-09 में (-)36.2 प्रतिशत था, उसके उलट कर वर्ष 2009-10 में 20.7 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है।

II.4 वार्षिक अनुमानों की तुलना में तिमाही आँकड़े निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) में वृद्धि में वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही में उसकी पिछली तिमाही और पिछले वर्ष की तदनुकूल तिमाही, दोनों, से काफी नरमी दर्शाते हैं। ग्रामीण आमदनी और खाद्य-कीमतों पर, और इसीलिए उपभोग मांग पर, कृषि उत्पादन में कमी के प्रतिकूल प्रभाव को इसका कारण माना जा सकता है। सरकारी अंतिम उपभोग व्यय (जीएफसीई) में वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही में पिछले वर्ष की तुलनीय तिमाही से तेज गिरावट दर्ज की गयी, जिसका कारण उस समय किये गये राजकोषीय उद्दीपक उपायों के आधारभूत प्रभाव को माना जा सकता है। तथापि, तिमाही के दौरान निवेश मांग में औद्योगिक सुधार के साथ-साथ और तेजी आयी; सकल अचल पूँजी निर्माण वर्ष 2008-09 की तदनुकूल तिमाही के 0.8 प्रतिशत की तुलना में 8.9 प्रतिशत तक बढ़ा।

### राजकोषीय नीति के माध्यम से मांग का प्रबंध

केंद्र सरकार के वित्त : वर्ष 2009-10 और 2010-11

II.5 वर्ष 2009-10 के दौरान, भले ही केंद्र सरकार के प्रमुख घाटा संकेतकों में और बढ़ोतरी होने के संदर्भ में विस्तारक राजकोषीय स्वरूप बना रहा, कुल व्यय में काफी गिरावट आयी, जिसकी अगुआई राजस्व व्यय में की गयी काफी कटौती ने की (सारणी II.2)। वर्ष 2009-10 (आरई) के दौरान सभी घाटा संकेतकों में बढ़ोतरी का एक प्रमुख कारण, व्यय की वृद्धि में नरमी के बावजूद,

अप्रत्यक्ष कर की दर में कटौती के परिणामस्वरूप कर-प्राप्तियों में काफी कम वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था में मंदी का राजस्व प्रभाव था। तथापि, न्यून अप्रत्यक्ष करों ने, विनिर्मित उत्पादों की कीमतों को कम करते हुए, अप्रत्यक्ष रूप से मांग को बढ़ाने में मदद की होगी।

II.6 वर्ष 2010-11 के लिए बजट-निर्धारित योजनाएँ, मध्यावधि वृद्धि के लिए राजकोषीय अनुशासन और मुद्रास्फीति दृष्टिकोण को पहचानते हुए, तथा जीडीपी वृद्धि में सुधार के स्पष्ट संकेतों को भी ध्यान में रखते हुए, नपे-तुले ढंग से राजकोषीय उद्दीपक उपायों के निकास की शुरुआत की ओर इंगित करती हैं। यह सभी घाटा संकेतकों के आकार में परिकल्पित कमी को प्रतिबिंबित करता है (सारणी II.2)। कुल व्यय के पिछले दो वर्षों की तुलना में काफी कम दर पर बढ़ने की संभावना है। पूँजीगत व्यय में वृद्धि, जिसमें वर्ष 2009-10 में काफी बढ़ोतरी की गयी थी, को पुनः वर्ष 2010-11 में ऊर्ध्वमुखी रूप से संशोधित किया गया है। इससे मध्यावधि वृद्धि संभावनाओं में मदद मिलने की उम्मीद हो सकती है, भले ही सरकारी व्यय की वृद्धि में समग्र रूप से नरमी आये।

II.7 राजस्व के मोर्चे पर भी, वर्ष 2010-11 के लिए बजट में पेट्रोलियम से इतर उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और पेट्रोलियम उत्पादों पर आधारिक शुल्क को वापस लेने की घोषणा की गयी है। अप्रत्यक्ष करों की इस वापसी के बाद विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में अनुमानित वृद्धि का निजी क्षेत्र की सकल मांग पर कुछ अवमंदन प्रभाव हो सकता है। इस प्रकार घटे हुए सरकारी व्यय के प्रभाव के साथ सकल मांग में राजकोषीय नीति संबंधी उपायों से पिछले दो वर्षों की तुलना में बहुत कम समर्थन प्राप्त हो सकता है। इस बात को पहचाने जाने की आवश्यकता है कि बड़े राजकोषीय उद्दीपक एक आपवादिक परिस्थिति, अर्थात्,

सारणी II.2: केंद्र सरकार के वित्त						
मद	वृद्धि-दर (प्रतिशत)			जीडीपी में प्रतिशत		
	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)	2008-09	2009-10 (संअ)	2010-11 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल व्यय	30.5	15.6	8.5	15.9	16.6	16.0
2. राजस्व व्यय	33.5	14.2	5.8	14.2	14.7	13.8
3. पूँजीगत व्यय	9.0	27.8	30.2	1.6	1.9	2.2
4. योजनेतर व्यय	29.0	16.0	4.1	10.9	11.5	10.6
5. योजना व्यय	34.2	14.5	18.4	4.9	5.1	5.4
6. राजस्व प्राप्तियाँ	-0.3	6.9	18.2	9.7	9.4	9.8
i) कर राजस्व (निवल)	0.9	4.9	14.8	8.0	7.5	7.7
ii) करेतर राजस्व	-5.3	15.7	32.0	1.7	1.8	2.1

संअ: संशोधित अनुमान

बअ: बजट अनुमान

वैश्विक संकट की छूट की वह जोखिम, जो हमारी वृद्धि को दुर्बल करता, के प्रत्युत्तर में था। लेकिन स्वभावतः इन उपायों को अस्थायी होना था और कालांतर में इन्हें वापस ले लिया जाना था, ताकि मध्यावधि में धारणीय उच्च वृद्धि के साधन के रूप में ठोस राजकोषीय स्थिति सुनिश्चित हो सके।

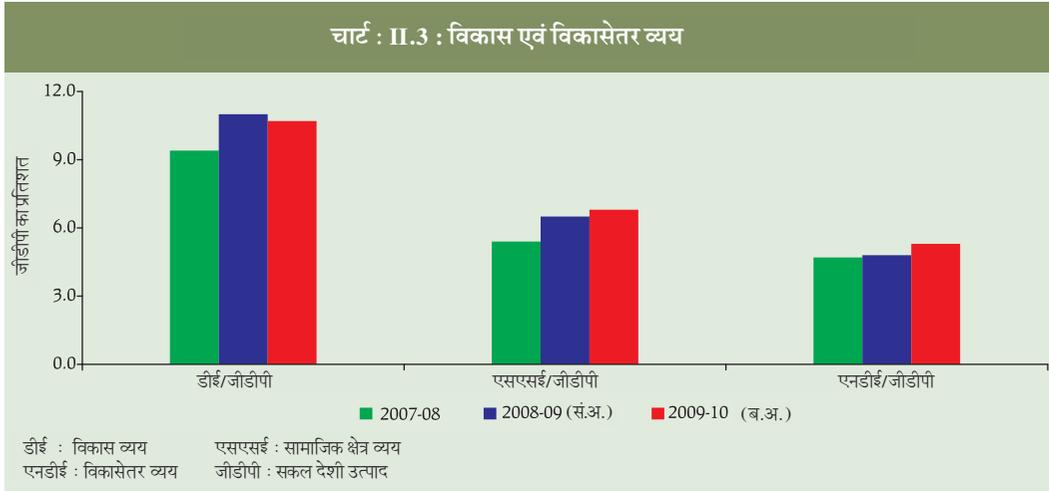
II.8 इसके अतिरिक्त, बजट में कुछ प्रत्यक्ष कर उपायों की घोषणा की गयी, यथा, आयकर स्लैबों में वृद्धि, जो जीडीपी के लगभग 0.4 प्रतिशत तक निजी प्रयोज्य आय में बढ़ोतरी करता। इसका कुछ सकारात्मक प्रभाव सकल मांग पर पड़ेगा। बजट में अनेक मदों, यथा, चुनिंदा कृषिजन्य वस्तुओं और संबद्ध क्षेत्र, पर्यावरण अनुकूल उत्पादों, शहरी परिवहन के लिए मोनो रेल परियोजना, मोबाइल फोन और चिकित्सीय उपकरणों के घरेलू विनिर्माण, के संबंध में रियायती सीमा-शुल्क और सेवा-कर में छूट की घोषणा किये जाने से निजी क्षेत्र की सकल मांग पर उसका प्रभाव होगा, जबकि इन वस्तुओं के उत्पादन में प्रोत्साहन प्राप्त होगा।

#### राज्य वित्त

II.9 राज्य सरकारों ने भी वर्ष 2008-09 की दूसरी छमाही में आर्थिक मंदी के मद्देनजर बढ़े हुए सरकारी

खर्च की आवश्यकता को पहचाना (चार्ट II.3)। वर्ष 2009-10 (बीई) में राजस्व प्राप्तियों में 9.1 प्रतिशत तक बढ़ोतरी वर्ष 2008-09 (बीई) में दर्ज की गयी, जो वर्ष 2008-09 (आरई) में दर्ज की गयी 18.3 प्रतिशत की बढ़ोतरी से कम थी। आर्थिक मंदी ने केंद्र से राज्यों को कर-राजस्व के सांविधिक अंतरण को भी प्रभावित किया।

II.10 राज्य सरकारों को अतिरिक्त पूँजी निवेश करने और घरेलू सकल मांग बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिये जाने की दृष्टि से उन्हें वर्ष 2008-09 में जीएसडीपी के 0.5 प्रतिशत और वर्ष 2009-10 में 0.5 प्रतिशत की सीमा तक अतिरिक्त बाजार उधार जुटाने की अनुमति दी गयी। तथापि, पूँजीगत व्यय के लिए वर्ष 2009-10 के बजट अनुमानों में ये गतिविधियाँ प्रतिबिंबित होती नहीं दिखती हैं; जीडीपी के अनुपात के रूप में पूँजीगत व्यय वर्ष 2008-09 के बजट (आरई) में 3.8 प्रतिशत से कम हो कर वर्ष 2009-10 के बजट में 3.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है। वर्ष 2009-10 के दौरान जिस अतिरिक्त कारक ने राज्य वित्त को सकल मांग के लिए सकारात्मक निहितार्थ के साथ प्रभावित किया, वह है छोटे केंद्रीय वेतन आयोग/राज्य वेतन आयोग की सिफारिशें।



**संयुक्त राजकोषीय स्थिति**

II.11 वर्ष 2009-10 के दौरान राजकोषीय स्वरूप विस्तारक बना रहा, ताकि सकल मांग बढ़ायी जा सके और उसके फलस्वरूप आर्थिक मंदी को रोका जा सके। इसके परिणामस्वरूप वर्ष 2009-10 (बीई) के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों का संयुक्त राजकोषीय घाटा वर्ष 2008-09 (आरई) के 8.5 से बढ़कर 9.7 प्रतिशत हो गया (सारणी II.3)। हालाँकि सरकारी

खर्च में तगड़े विस्तार में उच्चतर घाटा परिलक्षित नहीं हुआ, क्योंकि राजस्व प्राप्तियों में काफी गिरावट का प्रदर्शन हुआ (सारणी II.4)। वर्ष 2008-09 (आरई) के विपरीत, जब सरकारी उपभोग व्यय को प्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने पर काफी जोर दिया गया था, वर्ष 2009-10 (बीई) के दौरान कुल संयुक्त सरकार व्यय में तीव्र गिरावट आयी, विशेष रूप से राजस्व व्यय पर नियंत्रण के कारण। इस प्रकार, सकल मांग

**सारणी II.3: प्रमुख राजकोषीय संकेतक**

(जीडीपी का प्रतिशत)

वर्ष	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा	सकल राजकोषीय घाटा	बकाया देयताएं
1	2	3	4	5
<b>केंद्र</b>				
2007-08 (वास्तविक)	-0.9	1.1	2.5	57.3
2008-09 (वास्तविक)	2.6	4.5	6.0	56.7
2009-10 सं.अ.	3.2	5.3	6.7	57.0
2010-11 ब.अ.	1.9	4.0	5.5	56.9
<b>राज्य</b>				
2007-08 (वास्तविक)	-0.5	-0.9	1.5	26.8
2008-09 सं.अ.	0.7	-0.2	2.6	26.2
2009-10 ब.अ.	1.3	0.5	3.2	26.5
<b>संयुक्त</b>				
2007-08 (वास्तविक)	-1.1	0.2	4.1	72.0
2008-09 सं.अ.	3.4	4.1	8.5	71.6
2009-10 ब.अ.	4.3	5.1	9.7	73.2

सं.अ. : संशोधित अनुमान    ब.अ. : बजट अनुमान

सारणी II.4: संयुक्त वित्त						
मद	वृद्धि दर (प्रतिशत)			जीडीपी का प्रतिशत		
	2007-08	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)	2007-08	2008-09 (संअ)	2009-10 (बअ)
1	2	3	4	5	6	7
1. कुल व्यय	18.7	27.4	12.9	26.6	30.1	30.7
2. राजस्व व्यय	14.9	31.9	13.3	21.7	25.3	26.0
3. पूंजीगत व्यय	38.5	8.0	10.4	4.9	4.7	4.7
4. योजनेतर व्यय	16.2	11.3	20.9	11.9	11.8	12.9
5. विकास व्यय	20.8	40.9	7.6	14.4	17.9	17.5
6. राजस्व प्राप्तियाँ	21.1	11.3	8.8	21.5	21.2	20.9
i) कर राजस्व (निवल)	21.2	10.5	5.8	17.7	17.4	16.7
ii) करेतर राजस्व	20.5	15.2	22.1	3.7	3.8	4.2

संअ : संशोधित अनुमान

बअ : बजट अनुमान

की वृद्धि में सरकारी व्यय का प्रत्यक्ष योगदान पिछले वर्ष की तुलना में दुर्बल हुआ।

#### कारपोरेट कार्यसंपादन

II.12 आर्थिक मंदी के चरण में निजी मांग का नरम होना कारपोरेट विक्रय आँकड़ों से भी स्पष्ट था। तथापि, वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही में चुनिंदा गैर-वित्तीय गैर सरकारी सूचीबद्ध कंपनियों की वर्ष-दर-वर्ष विक्रय वृद्धि पिछली पाँच तिमाहियों में सबसे ऊँची रही। मौसमी रूप से समायोजित आनुक्रमिक विक्रय वृद्धि में भी पिछली तिमाही से सुधार दिखाई पड़ा। विक्रय वृद्धि में उछाल से निजी मांग में सुधार होने का संकेत मिलता है। न्यून ब्याज दर प्रणाली को प्रतिबिंबित करते हुए ब्याज व्यय में भी काफी कमी वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही में आयी, जिसने कर-पश्चात् लाभ में सुधार में योगदान किया। वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही में सकल और निवल लाभ क्रमशः 60 और 99.3 प्रतिशत तक बढ़े, जिसमें विशेष रूप से पिछले वर्ष की इसी तिमाही, जब लाभ में महत्वपूर्ण रूप से ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गयी थी, के न्यून आधारभूत प्रभाव से मदद मिली (सारणी II.5)। लाभ के आँकड़े सरकार द्वारा पिछले वर्ष के लागत कटौती उपक्रमों से भी प्रभावित हुए। जबकि निवल लाभ में वर्ष-दर-वृद्धि न्यून आधारभूत प्रभाव से प्रभावित हुई, तीसरी तिमाही में आनुक्रमिक निवल लाभ पिछली तिमाही से थोड़ा बढ़ा।

II.13 विक्रय में तगड़े उछाल को प्रतिबिंबित करते हुए विक्रय की तुलना में स्टॉक के अनुपात में परिवर्तन वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही में कम हुआ (चार्ट II.4)। यह प्रवृत्ति विक्रय के संबंध में इन्वेंटरी चक्र का चित्रण करता है, और इसीलिए, चक्र में अधोमुखी उतार-चढ़ाव विक्रय में वृद्धि और इन्वेंटरी स्टॉक में कमी को प्रतिबिंबित कर सकता है।

#### बाह्य मांग

II.14 वर्ष 2009-10 में निवल निर्यात (वस्तुओं और सेवाओं का) ने जीडीपी वृद्धि में धनात्मक योगदान (20.4 प्रतिशत) किया, जबकि वर्ष 2008-09 में इसने लगभग 36.2 प्रतिशत का ऋणात्मक योगदान किया था (चार्ट II.2)। वर्ष 2009-10 की पहली तीन तिमाहियों में पैटर्न में यह पुनरुत्थान निर्यात की तुलना में आयात में तेज संकुचन के कारण हुआ, भले ही निरपेक्ष दृष्टि से आयात निर्यात से अधिक होता रहा, जिसके चलते निवल निर्यात ऋणात्मक रहा। निर्यात वृद्धि वर्ष 2009-10 की तीसरी तिमाही में ऋणात्मक बनी रही, लेकिन संकुचन की दर पूर्ववर्ती तिमाहियों से कम हुई, जिससे बाह्य मांग में सुधार के संकेत मिलते हैं। आयात वृद्धि का निर्यात वृद्धि की तुलना में उच्चतर दर पर सिकुड़ना जारी रहा, लेकिन गिरावट की दर, निर्यात के मामले की तरह, वर्ष

सारणी II.5: गैर सरकारी गैर वित्तीय सूचीबद्ध कंपनियों का कार्यसंपादन

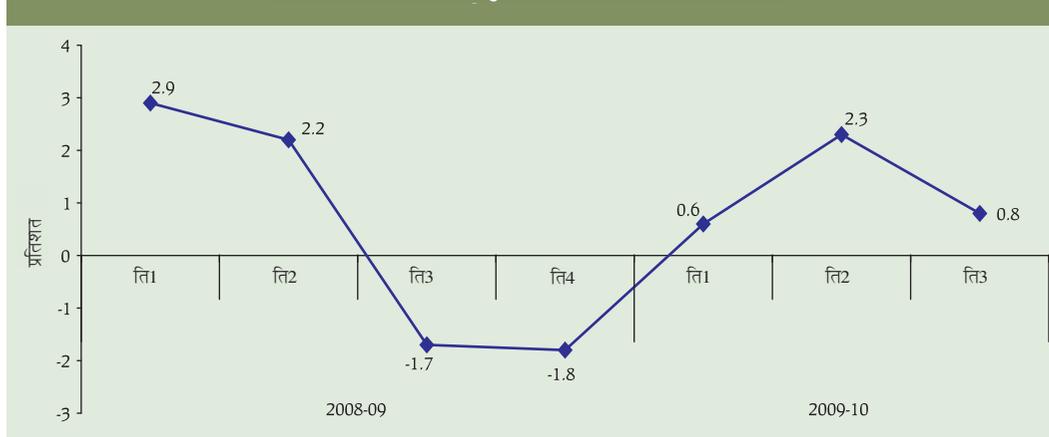
मद	(वृद्धि दर/अनुपात प्रतिशत में)							
	2008-09	2008-09				2009-10		
		ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
बिक्री	17.2	29.3	31.8	9.5	1.9	-0.9	0.1	22.5
अन्य आय*	6.6	-8.4	-0.6	-4.8	39.4	50.2	6.0	7.4
व्यय	19.5	33.5	37.5	12.6	-0.5	-4.4	-2.5	20.6
मूल्यहास का प्रावधान	17.4	15.3	16.5	16.8	19.6	21.5	20.7	21.6
सकल लाभ	-4.2	11.9	8.7	-26.7	-8.8	5.8	10.9	60.0
ब्याज भुगतान	57.3	58.1	85.3	62.9	36.5	3.7	-1.0	-12.3
कर-पश्चात् लाभ	-18.4	6.9	-2.6	-53.4	-19.9	5.5	12.0	99.3
<b>चुनिंदा अनुपात</b>								
बिक्री की तुलना में स्टॉक में परिवर्तन #	0.4	2.9	2.2	-1.7	-1.8	0.6	2.3	0.8
बिक्री की तुलना में सकल लाभ	13.3	14.5	13.5	11.0	13.7	15.7	14.9	14.3
बिक्री की तुलना में कर-पश्चात् लाभ	8.1	9.7	8.6	5.3	8.1	10.2	9.4	8.8
बिक्री की तुलना में ब्याज	3.1	2.4	2.9	3.8	3.2	2.8	3.1	2.7
सकल लाभ की तुलना में ब्याज	23.6	16.8	21.5	34.6	23.3	18.0	20.5	19.1
याज व्याप्ति (अवधि)	4.2	6.0	4.6	2.9	4.3	5.6	4.9	5.2

# उन कंपनियों के लिए, जो इस मद की स्पष्ट रिपोर्ट करती हैं।  
\* अन्य आय में असाधारण आय/व्यय शामिल नहीं है, यदि उसकी रिपोर्ट स्पष्ट रूप से की जाये।  
**टिप्पणी:** यद्यपि प्रत्येक अवधि में शामिल कंपनियों की संख्या और संरचना भिन्न-भिन्न है, फिर भी कंपनियों के सामान्य सेट के लिए संदर्भाधीन अवधि के लिए पिछले वर्ष की तदनुकूल अवधि की तुलना में वृद्धि दर उनके स्तर में प्रतिशत परिवर्तन को दर्शाती है।

2009-10 की तीसरी तिमाही में नरम हुई। तथापि, निवल निर्यात का धनात्मक योगदान आनेवाले वर्ष में प्रत्यावर्तित हो सकता है, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार विश्व अर्थव्यवस्था से पहले होने की संभावना को देखते हुए निर्यात की तुलना में आयात के अधिक बढ़ने की

संभावना है। अप्रैल-फरवरी (2009-10) के दौरान 95.7 बिलियन अमरीकी डॉलर पर वणिज्जक माल व्यापार घाटा अप्रैल-फरवरी (2008-09) में हुए 114.7 बिलियन अमरीकी डॉलर पर घाटे की तुलना में 16.6 प्रतिशत कम हुआ, जिसका कारण था इस अवधि के दौरान

चार्ट II.4 : बिक्री की तुलना में विक्रेय माल में परिवर्तन



निर्यात की तुलना में आयात में तेज गिरावट आना। वणिज्य माल व्यापार के आँकड़े भी मांग में वृद्धि में निवल निर्यात के योगदान में प्रत्यावर्तन को परिपुष्ट करते हैं। बाह्य मांग की स्थितियों के संबंध में विस्तृत चर्चा अध्याय III में की गयी है।

II.15 इस प्रकार सकल मांग और इसके विभिन्न घटकों के रुझान के समग्र मूल्यांकन से पता चलता है कि जबकि आर्थिक सुधार में विस्तारक सरकारी व्यय का समर्थन काफी संयत होने लगा है, निजी उपभोग मांग के लिए आवश्यक है कि वह वृद्धि में तीव्र आवेग प्रदर्शित करे। निवेश मांग में तेजी आयी है और इसमें और भी तेजी आने की उम्मीद है। हाल की अवधि में कारपोरेट विक्रय में बड़ा उछाल तथा उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन

में तगड़ी वृद्धि निजी मांग में सुधार की ओर इंगित करते हैं। वर्ष 2010-11 के लिए केंद्रीय बजट में संकेत किया गया है कि वर्ष 2010-11 में सकल मांग का समर्थन करने में राजकोषीय नीतिगत उपायों के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष प्रभाव पूर्ववर्ती दो वर्षों की तुलना में काफी कम होंगे। तथापि, वर्ष 2010-11 के लिए केंद्रीय बजट में आयोजित राजकोषीय विकास, मध्यावधि वृद्धि के दृष्टिकोण में सुधार लाने में योगदान करेगा और पूँजीगत व्यय के लिए आयोजित महत्वपूर्ण रूप से सुदृढ़ वृद्धि भी संवृद्धि को उद्दीप्त करेगी। विस्तारक राजकोषीय एवं समंजनकारी मौद्रिक नीति दृष्टिकोण से नपे-तुले विकास के साथ-साथ उपभोग तथा निवेश मांग का तेज होना भी वृद्धि की गति को बनाये रखने के लिए आवश्यक होगा।